५१ फीट की दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन जुलूस में खूनी संग्राम

भाजपा नेताओं के बीच धारदार हथियार चले, भाजायुमो मंडल अध्यक्ष जनपद सदस्य और उनके परिजन घायल; तीन की हालत गंभीर

जबलपुर, (एजेंसी)। आस्था के उत्सव में निकला ५१ फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस शुक्रवार देर शाम उस समय हिंसक टकराव का गवाह बन गया, जब बरेला थाना क्षेत्र के ग्राम बम्हनी में भाजपा से जुड़े दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद गाली-गलौज से बढ़कर धारदार हथियारों से हमले तक पहुंच गया। खूनी संघर्ष में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष प्रवेश पटेल, जनपद सदस्य रामेश्वर साहू, उनके भाई और परिवार की महिलाओं सहित कई लोग घायल हो गए। तीन घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विसर्जन जुलूस के बीच भड़की पुरानी रंजिश

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, ग्राम बम्हनी में स्थापित ५१ फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए शुक्रवार को चल समारोह निकाला गया था। इसी दौरान कुछ लोगों के बीच विवाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि पहले से चली आ रही रंजिश ने इस विवाद को और भड़का दिया। इसके बाद भाजपा से जुड़े जनपद सदस्य रामेश्वर साहू और भाजयुमो मंडल अध्यक्ष प्रवेश पटेलके पक्ष के लोग आमने-सामने आ गए।

रामेश्वर साहू जिला पंचायत सदस्य रानी साहू के पति बताए जाते हैं। दोनों पक्षों के बीच पहले तीखी बहस और गाली-गलौज हुई, फिर मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। हालांकि, विवाद की वास्तविक शुरुआत किस बात से हुई और हमला किसने पहले किया, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

दोनों पक्षों ने बताई अपनी पीड़ा

घटना के बाद प्रवेश पटेल सहित कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई। वहीं, रामेश्वर साहू ने भी खुद को घायल बताते हुए पुलिस से शिकायत की है। उनके भाई प्रहलाद साहू के भी अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी है। इस तरह मामला केवल एक पक्ष के घायल होने तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों पक्षोंके बीच गंभीर टकरावका रूप ले चुका है।

घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तीन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि, घायलों की कुल संख्या, उनकी चोटों की प्रकृति और सभी की वर्तमान स्थिति की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

देर रात तक पुलिस के सामने चुनौती

घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनने और राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस पर दबाव बनाए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों से जुड़े लोगों की सक्रियता के बीच देर रात तक पुलिस को स्थिति संभालने में मशक्कत करनी पड़ी।सबसे अहम सवाल यह है कि बरेला पुलिस ने मामले में किस-किस पक्ष की शिकायत दर्ज की है? क्या एक पक्ष की एफआईआर दर्ज हुई है या दोनों पक्षों की शिकायतों पर अलग-अलग प्रकरण कायम किए गए हैं? उपलब्ध जानकारी से यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।

फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की आधिकारिक कार्रवाई, दर्ज धाराओं और आरोपियों के संबंध में पुष्ट जानकारी सामने आना बाकी है। धार्मिक आयोजन के दौरान हुई इस हिंसा ने गांव के माहौल के साथ-साथ स्थानीय राजनीतिक हलकों में भी हलचल पैदा कर दी है। अब निगाहें पुलिस जांच पर हैं, जिससे विवाद की असली वजह और हमले की जिम्मेदारी तय हो सकेगी।

'अराजकता' रोको-लोकतंत्र अपनाओ के लगाए नारे

भोपाल, (एजेंसी)। भोपाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की भोपाल महानगर इकाई ने आज देशभर में हो रहे आंदोलनों के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। 'अराजकता रोको, लोकतंत्र अपनाओ' के नारे के साथ किए गए प्रदर्शन में संगठन ने संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे कथित अराजक हमलों का विरोध किया।

रैली टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुई और अटल पथ होते हुए न्यू मार्केट पहुंची। यहां टीटी नगर थाने के सामने

अभाविपने निकाली रैली, टीटीनगर में प्रदर्शन, आंदोलनोंके जरिए युवाओं को गुमराह करनेका लगाया आरोप

से गुजरते हुए रैली न्यू मार्केट चौराहे पर पहुंची, जहां सभा आयोजित की गई। यहां कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कॉकरोज जनता पार्टी और कांग्रेस देश का माहौल खराब कर रही हैं। सभा में अभाविप के पदाधिकारियों ने हाल के दिनों में दिल्ली सहित देश के विभिन्न स्थानों पर हुए आंदोलनों का विरोध किया। उन्होंने कांग्रेस और संबंधित संगठनों पर आंदोलनों के जरिए युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। पदाधिकारियों ने युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जागरूक रहने की अपील की।

निजी मेडिकल कालेजों में ३८७ सीटें बढ़ीं, सरकारी में १२ घटीं

नीट पीजी: संस्थागत कोटे से प्रवेश का गणित बदला
सरकारी कालेजों में सीटें कम, निजी में बड़ा इजाफा

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में नीट पीजी काउंसलिंग के पहले चरण में मेडिकल कॉलेजों की सीटों का गणित इस बार अभ्यर्थियों के लिए नई चुनौती लेकर आया है। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमडी-एमएस की सीटें पिछले साल के मुकाबले १२ घट गई हैं, जबकि निजी मेडिकल कॉलेजों में ३८७ सीटों का इजाफा हुआ है। कुल २१४१ सीटों पर प्रवेश होना है, लेकिन सीटों के बढऩे और घटने का असर सभी अभ्यर्थियों पर एक जैसा नहीं पड़ेगा। सरकारी कॉलेजों में सीमित सीटों और बड़ी संख्या में दावेदारों के कारण प्रतिस्पर्धा बढऩे की आशंका है। दूसरी ओर, निजी कॉलेजों में सीटें बढऩे के बावजूद आरक्षण रोस्टर और संस्थागत कोटे की व्यवस्था ने प्रवेश के समीकरण बदल दिए हैं।

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा (डीएमई) ने पहले चरण की स्टेट लेवल काउंसलिंग के लिए सीट चार्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए च्वाइस फिलिंग और सीट लॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार २९ अक्टूबर को सीट आवंटन किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस बार प्रदेश के १५ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमडी-एमएस की कुल ७२८ सीटें उपलब्ध हैं। पिछले साल इनकी संख्या ७४० थी। यानी सरकारी संस्थानों में १२ सीटों की कमी आई है। इसके उलट १२ निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटें १०२६ से बढक़र १४१३ हो गई हैं। इस तरह निजी संस्थानों में ३८७ अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हुई हैं। सीटों के इस अंतर का असर प्रवेश की प्राथमिकताओं पर पड़ सकता है। सामान्य तौर पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कम फीस और उपलब्ध सुविधाओं के कारण अभ्यर्थियों की पहली पसंद रहती है। ऐसे में सरकारी सीटों की संख्या घटने से इन संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा और कठिन हो सकती है। निजी कॉलेजों में सीटें बढऩे से कुल उपलब्धता जरूर बढ़ी है, लेकिन वहां प्रवेश की संभावना को कोटे और संबंधित नियमों के संदर्भ में देखना होगा।

निजी कालेजों को संस्थागत कोटे से भी फायदा

निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की वृद्धि के साथ इन-सर्विस और संस्थागत कोटे की व्यवस्था भी चर्चा में है। जारी सीट चार्ट के मुताबिक निजी कॉलेजों में इन-सर्विस कोटे के लिए ३० प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी गई हैं। इनमें २०१ सीटों पर इन-सर्विस अभ्यर्थियों के बीच संस्थागत कोटे को वरीयता दिए जाने की जानकारी है। इसके अलावा २६९ सीटें ओपन संस्थागत कोटे में रखी गई हैं। इस तरह कुल ४७० सीटों पर संस्थागत अभ्यर्थियों को किसी न किसी रूप में लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, इन सीटों पर वास्तविक पात्रता और आवंटन संबंधित आरक्षण नियमों तथा काउंसलिंग के प्रावधानों के अनुसार ही तय होगा। यही व्यवस्था ओपन श्रेणी के उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो मध्य प्रदेश के सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की उम्मीद लगाए हुए हैं। सीटों की कुल संख्या बढऩे के बावजूद यह जरूरी नहीं कि सभी सीटें हर अभ्यर्थी के लिए समान रूप से उपलब्ध हों।

मूल निवासी और संस्थागत कोटे के बीच उलझा प्रवेश का समीकरण

काउंसलिंग में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव संस्थागत कोटे को लेकर सामने आया है। पहले स्टेट कोटे की सीटों पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था थी। पात्र स्थानीय अभ्यर्थियों की उपलब्धता नहीं होने पर दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को अवसर मिल सकता था। नई व्यवस्था में मध्य प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए भी संस्थागत कोटे के तहत दावेदारी का रास्ता खुलता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू व्यवस्था के संदर्भ में डीएमई की मेरिट सूची में संस्थागत कोटे के लिए पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या महत्वपूर्ण हो गई है। जारी मेरिट सूची में कुल ४७७६ अभ्यर्थियों के नाम हैं। इनमें २२५५ ऐसे हैं, जिन्होंने ओपन श्रेणी के साथ संस्थागत कोटे में भी पंजीकरण कराया है। इस श्रेणी में पात्रता का निर्धारण केवल मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने के आधार पर नहीं किया जाएगा। संबंधित संस्थागत पात्रता के नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों की दावेदारी पर विचार होगा। इस बदलाव से प्रवेश प्रक्रिया में मूल निवासी और संस्थागत अभ्यर्थियों के बीच सीटों की दावेदारी का समीकरण बदल सकता है। हालांकि, संस्थागत कोटे के सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलना तय नहीं है। अंतिम परिणाम मेरिट, पात्रता, उपलब्ध सीटों और च्वाइस फिलिंग पर निर्भर करेगा।

४७७६ दावेदारों के सामने सरकारी कॉलेजों की ४८५ ओपन सीटें

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की तस्वीर देखें तो प्रतिस्पर्धा का दबाव स्पष्ट है। १५ सरकारी कॉलेजों की ७२८ सीटों में ४८५ ओपन श्रेणी के लिए हैं, जबकि २४३ सीटें इन-सर्विस कोटे के तहत आरक्षित हैं। दूसरी ओर, काउंसलिंग के लिए ४७७६ अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। इन आंकड़ों के आधार पर सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों के बीच सरकारी कॉलेजों की ओपन सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा का दबाव समझा जा सकता है। हालांकि, सभी अभ्यर्थी समान श्रेणी में पात्र नहीं हैं और उनकी रैंक, आरक्षण तथा पसंद के आधार पर वास्तविक प्रतिस्पर्धा अलग-अलग होगी। निजी कॉलेजों में इन-सर्विस और संस्थागत कोटे की व्यवस्था के कारण ओपन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीटों का आकलन भी जरूरी होगा। ऐसे में केवल कुल सीटों की संख्या देखकर प्रवेश की संभावना तय करना सही नहीं होगा।

पीजी डिप्लोमा की २६ सीटों पर भी प्रवेश

एमडी-एमएस के साथ इस बार पीजी डिप्लोमा पाठयक्रमों के लिए भी काउंसलिंग की जा रही है। प्रदेश के १२ जिलों के जिला अस्पतालों में संचालित इन पाठयक्रमों की कुल २६ सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। पीजी डिप्लोमा की सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए एक अतिरिक्त विकल्प हैं, जो स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश चाहते हैं। हालांकि, पाठयक्रम, संस्थान और उपलब्ध सीटों के अनुसार उनकी पसंद अलग हो सकती है। कुल मिलाकर, इस बार नीट पीजी काउंसलिंग में सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका वर्गीकरण और पात्रता का नियम बन गया है। सरकारी कॉलेजों में सीटें घटने, निजी संस्थानों में बढऩे और संस्थागत कोटे के नए समीकरणों के बीच अभ्यर्थियों को च्वाइस फिलिंग सावधानी से करनी होगी। २९ अक्टूबर को होने वाला सीट आवंटन बताएगा कि इन बदलावों का वास्तविक लाभ किन अभ्यर्थियों को मिलता है।

मृगवास के बांकखेड़ा में रास्ते के पुराने विवाद में युवक की बेरहमी से हत्या

गुना, (एजेंसी)। जिले के मृगवास थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बांकखेड़ा गांव में शुक्रवार देर रात रास्ते के पुराने विवाद ने खूनी रूप ले लिया। लंबे समय से चले आ रहे आपसी मनमुटाव के चलते एक पक्ष के दबंगों ने दूसरे पक्ष के युवक को घेरकर लाठी व धारदार लुहांगी से प्राणघातक हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की मौके पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई। घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है, वहीं पुलिस ने कुंभराज अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है।

हमलावरों ने घात लगाकर किया हमला

प्राप्त जानकारी के मुताबिक बांकखेड़ा गांव निवासी पवन लोधा (२८ वर्ष) पिता शिवलाल लोधा का गांव के ही कुछ लोगों से रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। दोनों पक्षों में इसे लेकर पूर्व में भी कहासुनी हो चुकी थी। शुक्रवार रात जब पवन गांव के रास्ते से गुजर रहा था, तभी विरोधी पक्ष के लोगों ने उसे अकेला पाकर घेर लिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने उस पर लाठी-डंडों और लोहे की लुहांगी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। अचानक हुए इस भीषण हमले में पवन संभल भी नहीं सका और अत्यधिक खून बह जाने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

पुलिस ने संभाला मोर्चा, आरोपियों पर शिकंजा कसा

घटना की सूचना मिलते ही मृगवास थाना पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को कुंभराज शासकीय अस्पताल भिजवाया, जहां शनिवार सुबह डॉक्टरों के दल ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामले की प्राथमिक जांच और परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने गांव के ही सागर सिंह (४० वर्ष) पिता कल्याण सिंह लोधा एवं कोमल सिंह (५० वर्ष) पिता बिहारी लाल लोधा सहित अन्य के खिलाफ हत्या की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। घटना के बाद से गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस मुस्तैद बनी हुई है।

भोपाल में थिंक गैस की लाइन में आग लगी

छोला इलाके में ब्रिज के पास लीकेज हुई; फायर टीम ने काबू पाया

भोपाल, (एजेंसी)। भोपाल के छोला इलाके से गुजरी थिंक गैस की लाइन में शनिवार दोपहर आग लग गई। इससे इलाके में हडक़ंप मच गया। सूचना मिलने पर फायर टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना दोपहर साढ़े १२ बजे की है। छोला ब्रिज के पास से भूमिगत थिंक पीएनजी लाइन गुजरी है। शनिवार दोपहर में यहां मेट्रो का काम चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जेसीबी से खुदाई के दौरान गैस लाइन लीकेज हुई। इस दौरान आग की लपटें १० फीट तक उठने लगी। गैस लाइन लीकेज होने से इलाके में हडक़ंप की स्थिति बन गई। ब्रिज पर लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने लोगों को दूर किया। वहीं, छोला फायर टीम मौके पर पहुंची। फायर फाइटर पंकज यादव समेत टीमने पानीसे आग बुझाई। इधर, थिंक कंपनी से लाइन बंद कराई। तब कहीं जाकर आग पूरी तरहसे बुझ सकी। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ महीने पहले शाहपुरा थाने के सामने भी लाइन लीकेज हो गई थी।

डामर के दाम दोगुने, एमपी में सड़क प्रोजेक्ट ठप

ठेकेदारों ने मांगी बढ़ी लागत, सरकार के फैसले का इंतजार

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध तथा क्षेत्रीय तनाव का असर अब मध्य प्रदेश में सडक़ निर्माण परियोजनाओं पर भी दिखाई देने लगा है। सडक़ बनाने में इस्तेमाल होने वाले डामर की कीमत छह महीने में लगभग दोगुनी हो गई है। इससे पहले तय दरों पर ठेके लेने वाली निर्माण कंपनियों के सामने लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। नतीजतन, कई सडक़ परियोजनाओं में डामरीकरण प्रभावित है और ठेकेदार अनुबंध की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। रतलाम-झाबुआ स्टेट हाईवे इसका एक उदाहरण है। करीब एक साल से निर्माणाधीन इस सडक़ पर अब तक डामरीकरण का काम शुरू नहीं हो पाया है। निर्माण कंपनी ने मध्य प्रदेश सडक़ विकास निगम (एमपीआरडीसी) से डामर की बढ़ी कीमतों के अनुरूप अनुबंध राशि संशोधित करने की मांग की है। उधर, रतलाम नगर निगम की २१ नई सडक़ों के निर्माण कार्य भी प्रभावित हुए हैं। इन सडक़ों का भूमिपूजन हो चुका है, लेकिन बढ़ी लागत के कारण ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सडक़ निर्माण में इस्तेमाल होने वाला डामर पेट्रोलियम रिफाइनिंग से प्राप्त होता है। कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति की परिस्थितियों में बदलाव का असर इसकी लागत पर पड़ सकता है। रतलाम में डामर मिक्सिंग प्लांट संचालित करने वाले वेंकटेश तिमन्ना के मुताबिक, छह महीने पहले डामर लगभग ४५ हजार से ५५ हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से मिल रहा था। अब अलग-अलग स्थानों पर इसकी कीमत ८५ हजार से १.०२ लाख रुपये प्रति टन तक पहुंच गई है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री महेंद्र सिंह चौहान के अनुसार, डामर की कीमत करीब ९० हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। सडक़ निर्माण और पुरानी सडक़ों की मरम्मत के लिए इसकी मांग बनी हुई है। कीमतों में इस उछाल से उन ठेकेदारों की मुश्किलें बढ़ी हैं, जिन्होंने पहले निर्धारित दरों पर सडक़ निर्माण के अनुबंध लिए थे। डामर की लागत बढऩे के बावजूद यदि अनुबंध की राशि नहीं बदलती, तो निर्माण कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ता है और कुछ मामलों में काम जारी रखना आर्थिक रूप से कठिन हो जाता है।डामर की उपलब्धता और कीमतों का असर केवल नई सडक़ों तक सीमित नहीं है।

टापर्स चुन रहे बीएएमएस और बीएचएमएस को

मेडिकल करियर की पसंद में बदल रहा ट्रेंड, निजी मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की महंगी सीटों से मोहभंग

भोपाल, (एजेंसी)। नीट में अच्छे अंक हासिल करने के बाद भी एमबीबीएस ही पहली पसंद हो, अब ऐसा जरूरी नहीं रह गया है। मध्य प्रदेश में मेडिकल काउंसलिंग के तीन मुख्य दौर पूरे होने के बाद सामने आए प्रवेश के रुझान बताते हैं कि कई मेधावी अभ्यर्थियों ने निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की महंगी सीट लेने के बजाय सरकारी आयुष कॉलेजों में बीएएमएस और बीएचएमएस को चुना है। इंदौर, उज्जैन और भोपाल के सरकारी आयुष संस्थानों में दाखिला लेने वाले कुछ अभ्यर्थियों के अंक नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और निजी एमबीबीएस संस्थानों के कटऑफ से भी अधिक रहे हैं। इस बदलाव के पीछे केवल एमबीबीएस में प्रवेश नहीं मिल पाना ही कारण नहीं है। निजी मेडिकल कॉलेजों की भारी फीस, सरकारी आयुष संस्थानों में कम खर्च पर पढ़ाई और आयुष चिकित्सा पद्धतियों में करियर की संभावनाएं भी अभ्यर्थियों की पसंद को प्रभावित कर रही हैं। हालांकि, सभी अभ्यर्थियों के लिए यह फैसला समान परिस्थितियों में लिया गया हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी के लिए आर्थिक दबाव अहम है, तो किसी के लिए सरकारी संस्थान में पढ़ाई प्राथमिकता है।

इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और भोपाल के एलएनसीटी सेवाकुंज जैसे निजी मेडिकल संस्थानों में सामान्य वर्ग की एमबीबीएस सीटें लगभग ४८४-४८५ अंकों पर बंद हुईं। इसके मुकाबले इंदौर के सरकारी अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज और भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज में बीएएमएस के कुछ शीर्ष अभ्यर्थियों के अंक ४९० से ५३५ के बीच रहे। यानी इन अभ्यर्थियों के पास अंकों के लिहाज से कुछ निजी एमबीबीएस कॉलेजों में प्रवेश की संभावना थी, लेकिन उन्होंने सरकारी आयुर्वेद कॉलेजों को चुना। यह अंतर मेडिकल शिक्षा में बदलती प्राथमिकताओं की ओर संकेत करता है। हालांकि, कटऑफ की तुलना संबंधित काउंसलिंग दौर, श्रेणी और सीट के प्रकार के संदर्भ में ही की जानी चाहिए।

नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के कटऑफ से भी आगे

मंदसौर, नीमच, श्योपुर और सिंगरौली के नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एससी, एसटी और सरकारी स्कूल कोटे के तहत कुछ अभ्यर्थियों को ३८० से ४५५ अंकों के बीच एमबीबीएस सीटें मिलीं। दूसरी ओर, सरकारी आयुष कॉलेजों में बीएएमएस और बीएचएमएस चुनने वाले कुछ अनारक्षित और ओबीसी अभ्यर्थियों के अंक ४६५ से ५३५ के बीच रहे। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि केवल अंकों के आधार पर मेडिकल कोर्स की पसंद तय नहीं हो रही। श्रेणी, कोटा, कॉलेज की उपलब्धता, फीस और अभ्यर्थी की व्यक्तिगत प्राथमिकता भी प्रवेश के फैसले में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

एमजीएम में चूके, लेकिन निजी कॉलेज की महंगी सीट भी नहीं चुनी

इंदौर के महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय (एमजीएम) में अनारक्षित श्रेणी का एमबीबीएस कटऑफ ६०७ अंक तक पहुंचा। वहीं सरकारी बीएएमएस कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले कुछ शीर्ष अभ्यर्थियों के अंक ५३० से ५३५ के आसपास रहे। इस तरह एमजीएम के बताए गए

जेल से छूटकर आए युवक ने मांगे ५ हजार रुपये, मना करने पर पीटा

जबलपुर, (एजेंसी)। गोहलपुर थाना क्षेत्र में खर्च के लिए पांच हजार रुपये नहीं देने पर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। अजीजगंज पसियाना निवासी २७ वर्षीय मोहम्मद मोहसिन खान ने पुलिस को बताया कि २२ अक्टूबर की रात करीब दो बजे डयूटी से घर लौटते समय रद्दी चौकी स्थित पंचशील स्कूल के पास जुबेर बादशाह, समीर करिया और समीर माडल मिले। जुबेर ने जेल से छूटकर आने और रुपये नहीं होने की बात कहते हुए पांच हजार रुपये मांगे। रुपये देने से मना करने पर तीनों ने गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की,।

युवती की मौत के बाद परिजनों का चक्काजाम, युवक पर प्रताड़ित करने का आरोप

एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर हनुमान चौराहे पर आधे घंटे तक प्रदर्शन; अधिकारियों के आश्वासन पर खुला जाम

गुना, (एजेंसी)। बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसी खुर्द में १९ वर्षीय युवती की मौत के बाद परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर परेशान करने और शादी के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। शनिवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजन शिकायत लेकर बजरंगगढ़ थाने पहुंचे। उनका आरोप है कि तीन बार थाने जाने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई और एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इससे नाराज परिजनों ने हनुमान चौराहे पर चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। समझाइश और कार्रवाई के आश्वासन के बाद करीब आधे घंटे में जाम खुल सका।

परिजनों के मुताबिक, घटना के समय परिवार के सदस्य खेत पर मक्का निकालने गए थे और युवती घर पर अकेली थी। शाम को जब वे वापस लौटे तो युवती मृत अवस्था में मिली। परिजनों का आरोप है कि गांव का एक युवक लंबे समय से उनकी बेटी को फोन पर बात करने और उससे शादी करने के लिए दबाव डालकर परेशान कर रहा था। उनका कहना है कि युवक कई बार घर में भी घुस आया था और शादी करने की बात कहकर धमकाता था।

परिवार का कहना है कि उन्होंने पहले भी युवक और उसके पिता को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन कथित तौर पर युवती को परेशान करना बंद नहीं हुआ। परिजनों के अनुसार, सामाजिक बदनामी के डर से उन्होंने पहले पुलिस में शिकायत नहीं की थी। अब बेटी की मौत के बाद वे संबंधित युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि वे शिकायत लेकर तीन बार बजरंगगढ़ थाने गए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने हनुमान चौराहे पर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। चक्काजाम की सूचना पर सीएसपी सैफा हाशमी और तहसीलदार मयंक तिवारी सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर उनकी शिकायत सुनी और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन जाम खोलने के लिए राजी हुए। सीएसपी सैफा हाशमी ने बताया कि बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसी खुर्द में १९ वर्षीय युवती की आत्महत्या का मामला सामने आया है। इसके बाद परिजनों ने चक्काजाम कर संबंधित युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि परिजनों के कथन लिए जा रहे हैं और मामले में पूरी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल युवती की मौत के कारणों और परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच पुलिस कर रही है। युवक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

रास्ते से पिकअप ले जाने पर विवाद, चालक पर पत्थर से हमला

जबलपुर, (एजेंसी)। बरगी थाना क्षेत्र के खुर्शी कैनाल मार्ग पर रास्ते को लेकर हुए विवाद में एक पिकअप चालक पर पत्थर से हमला कर उसे घायल करने का मामला सामने आया है। ग्राम मंगेली निवासी २१ वर्षीय अरविंद भूमिया ने पुलिस को बताया कि वह ग्राम मोहास निवासी प्रीति काटेरी की पिकअप चलाता है। २३ अक्टूबर को वह जनरेटर और डीजे का सामान लेकर ग्राम गोकलपुर जा रहा था। दोपहर करीब ३:४५ बजे खुर्शी गांव निवासी रविन्द्र मरावी ने उसे अंदर के रास्ते से पिकअप ले जाने से मना करते हुए गाली-गलौज की। विरोध करने पर रविन्द्र ने पत्थर से हमला कर उसके मुंह में चोट पहुंचाई और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

कांग्रेस में 'घर वापसी' पर सख्ती!

भाजपा में गए नेताओं के लिए आसान नहीं होगी राह, पहले देनी होगी राजनीतिक परीक्षा

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश की राजनीति में दल-बदल करने वाले नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कांग्रेस छोडक़र भाजपा में गए और अब दोबारा कांग्रेस में लौटने की इच्छा रखने वाले नेताओं के लिए वापसी का रास्ता आसान नहीं होगा। कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि अब किसी भी नेता को सीधे पार्टी में एंट्री नहीं मिलेगी। वापसी से पहले स्थानीय स्तर पर उसकी राजनीतिक भूमिका, पार्टी छोडऩे की परिस्थितियों और लौटने की वजहों की पड़ताल की जाएगी। कांग्रेस में प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक, भाजपा से कांग्रेस में लौटने के इच्छुक नेताओं के नाम सबसे पहले जिला समन्वय समिति के सामने रखे जाएंगे। समिति संबंधित नेता की राजनीतिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों पर विचार करेगी। इसके बाद ही वापसी के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। खबर के अनुसार, समिति में सर्वसम्मति से सहमति बनने पर प्रस्ताव आगे पीसीसी भेजा जाएगा। वहीं, समिति की ओर से आपत्ति आने पर संबंधित नेता की वापसी की राह मुश्किल हो सकती है। समिति यह देखेगी कि संबंधित नेता ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, किन परिस्थितियों में भाजपा में शामिल हुआ और अब दोबारा कांग्रेस में लौटना क्यों चाहता है। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही उसकी वापसी को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इस रुख से स्पष्ट है कि पार्टी स्थानीय संगठन की राय को महत्व देना चाहती है और वापसी के मामलों में राजनीतिक परिस्थितियोंकी अनदेखी नहीं करना चाहती।

सूत्रों के मुताबिक, भाजपा छोडक़र कांग्रेस में लौटने की संभावनाएं तलाश रहे कुछ नेता फिलहाल खुलकर सामने आने से बच रहे हैं।

भोपाल निगम परिषदमें कमीशनपर घमासान, भाजपा पार्षदोंने घेरी अध्यक्षकी आसंदी

नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी बोलीं- 'मैं कमीशन नहीं लेती, किसी से माफी नहीं मांगूंगी'
नए निगम मुख्यालय को २० साल तक किराए पर देने सहित कई प्रस्ताव बहुमत से पारित

भोपाल, (एजेंसी)। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक शनिवार को कमीशन संबंधी बयान को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गई। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी के 'मैं कमीशन नहीं लेती' कहने पर भाजपा पार्षद भडक़ गए और अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की आसंदी घेर ली। अध्यक्ष ने जकी से अपने शब्द वापस लेने और माफी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। विवाद के चलते सदन की कार्यवाही १५ मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बीच निगम के नए मुख्यालय के सर्विस ब्लॉक और कैफेटेरिया को अधिकतम २० साल तक किराए पर देने सहित कई प्रस्ताव बहुमत से पारित किए गए।

बैठक में सरकार द्वारा नियुक्त १२ एल्डरमैन और नए निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार का परिचय भी कराया गया। अहिरवार ने तीन दिन पहले ही पदभार संभाला है। बैठक की शुरुआत में ही जकी ने छुट्टी के दिन परिषद का सम्मेलन बुलाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने निगम एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि अवकाश के दिन सदन का संचालन नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष सूर्यवंशी की समझाइशके बाद कार्यवाही आगे बढ़ी।

प्रश्नकाल के बाद नए निगम मुख्यालय के सर्विस ब्लॉक और कैफेटेरिया को किराए पर देने के प्रस्ताव पर बहस शुर